उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की आटे की मिलों से मैदा रहित आटे की खरीद के बारे में किया गया भुगतान

*171. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार दिल्ली की आटा मिलों द्वारा बेचे जाने वाले मैदा रहित (रिजल्टेंट) आटे के लिए मिलों को किस दर पर भुगतान करती है ;

(ख) सरकार उत्तर प्रदेश की आटा मिलों से खरीदे जाने वाले मैदा रहित (रिजल्टेंट) आटे का भुगतान इन मिलों को किस दर पर करती है ;

(ग) सरकार उत्तर प्रदेश और दिल्ली की आटा मिलों को गेहूं की आपूर्ति किस दर पर करती है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश की आटा मिलों से कम दरों पर तथा दिल्ली की मिलों से ऊंची दरों पर मैदा रहित रिजल्टेंट आटा खरीदे जाने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति जितनी मात्रा में परिणामी आटा उठाया गया था, वह दिल्ली की रोलर फ्लोर मिलो ने 180/– रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए निकासी मूल्य पर सप्लाई किया जाता है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति जितनी मात्रा मे परिणामी आटा उठाया गया था वह उक्त राज्य की रोलर फ्लोर मिलों द्वारा 125/– रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निकासी मूल्य पर सप्लाई किया जाता है ।

(ग) रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं 208/– रुपये प्रति क्विंटल के समान मूल्य पर सप्लाई किया जाता है जिसमें कर शामिल नहीं हैं ।

(घ) सरकार द्वारा सप्लाई किए गए गेहूं में से रोलर फ्लोर मिलों द्वारा तैयार किए गए गेहूं के उत्पादों के निकासी मूल्य, उन्हें उपयुक्त मिलिंग मार्जिन देने के बाद राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । रोलर फ्लोर मिलों द्वारा तैयार किए गए गेहूं के सभी चार उत्पादों के लिए निर्धारित किए गए मूल्यों को ध्यान में रखने के बाद मिलिंग मार्जिन का हिसाब लगाया जाता है । तदनुसार, गेहूं के चार उत्पादों के मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं । हालांकि उन राज्यों में अनुमेय मिलिंग मार्जिन वही क्यों न हों ।

Stagnation in Marine Fish Production

*172. SHRIMATI SANYOGITA RANE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of stagnation in marine fish production;

(b) whether Government have identified constraints in the development of deep sea fishing ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken in this matter ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Average annual production of marine fish in the trienniam ending 1982 touched a record level of 14.81 lakh tonnes against the corresponding figures of 14.77 and 14.43 lakh tonnes in the preceeding two triennia.

(b) and (c) Major constraints in the development of deep sea fishing have been identified as :

(i) need for a massive investment of capital involving a high degree of risk ;

(ii) need for trained personnel ;

(iii) lack of adequate infrastructure of harvest and post harvest technology ;